

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255498  
SG-DL-E-17072024-255498असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 105
No. 34]	DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946	[N. C. T. D. No. 105

भाग II—I  
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

सं. 63/नियम/डीएचसी—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 11 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 18 के अंतर्गत पूर्व में बनाए गए नियमों को अधिक्रमित करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय न्यायाधीशगण निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

## 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ:-

- यह नियम दिल्ली लघु अपराध (विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण) नियम, 2024 कहलाएंगे।
- यह नियम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगे।
- यह नियम इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (1) "संहिता" से अभिप्रेत होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- (2) "अपराध" से वही अभिप्रेत होगा जो इसे संहिता में निर्दिष्ट किया गया है।
- (3) (क) "लघु अपराध" से अभिप्रेत है निम्नलिखित प्रावधानों में सूचीबद्ध अपराध:
  - (i) संहिता की धारा 359, तालिका I और II, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79, 82(1), 88, 117(2), 122(2), 125(ख), 127(3), 127(4), 127(6), 303(2), 306, 316(2), 316(3), 316(4), 317(2), 317(5), 318(2), 318(3), 318(4), 319(2), 322, 323, 325, 326(क), 347(2) और 351(3) के अंतर्गत अपराधों को छोड़कर;
  - (ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 194 और 125;
  - (ii) किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध जो दो साल के कारावास तक दंडनीय हैं।
  - (ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय किए जाने वाले किसी अन्य प्रकार के मामलों को भी आवंटित कर सकते हैं।
- (4) संहिता की धारा 2 में दी गई परिभाषाएं इन नियमों के लिए मान्य होंगी।

3. अर्हता: कोई व्यक्ति विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा जब तक कि वह विधि स्नातक न हो, तथा

- (1) ज़िला मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी न रह चुका हो; या
- (2) कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रयोग न कर चुका हो; या
- (3) कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रयोग न कर चुका हो; या
- (4) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय या इसके अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना में समूह 'क' के पद पर न रहा हो; या
- (5) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी विभाग में समूह 'क' के पद पर न रहा हो (उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने विधिक मामलों से सम्बंधित कार्य किया हो या जो विधिक मामलों से सम्बंधित विभाग में कार्य कर चुके हों); एवं
- (6) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान किए जाने की तिथि को 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका/चुकी हो।

स्पष्टीकरण:-

इन नियमों के प्रयोजन हेतु "विधि स्नातक" वह व्यक्ति है जो अधिवक्ता के रूप में नाम दर्ज कराने योग्य है।]

4. अयोग्यता: कोई व्यक्ति-

- (1) जो सरकार/दिल्ली उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत किसी श्रेणी व स्तर के पद पर न हो या न ही रह चुका हो तथा उसके पास ठीक पिछले नियम में उल्लिखित उससे जुड़ी योग्यता, यदि कोई हो, न हो; अथवा
- (2) जो राज्य या संघ सरकार या उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत किसी पद पर रहते हुए सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो या कदाचार के लिए उस पर बड़ी शास्ति लगाई हो; अथवा

- (3) जिसे उप-नियम (2) में उल्लिखित किसी पद पर रहते हुए नैतिक अपचारिता से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और सज़ा सुनाई गई हो या उस पर नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो और उसके खिलाफ़ कार्यवाही लंबित हो; या
- (4) जो उप-नियम (2) में उल्लिखित किसी पद पर रहते हुए मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या बधिर या मूक या अंधा हो या कुछ रोग या किसी अन्य संक्रामक रोग से पीड़ित हो; या
- (5) जो उप-नियम (2) में उल्लिखित किसी पद पर रहते हुए दिवालिया या निर्विवाद दिवालिया निर्णीत किया गया हो; या
- (6) जो नियम 3 के उप-नियम (1), (2), (3), (4) और (5) में उल्लिखित पद पर रहते हुए पेशेवर अधिवक्ता हो;

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान किए जाने हेतु योग्य नहीं होगा।

बशर्ते कि उप-नियम (6) में उल्लिखित कोई पेशेवर अधिवक्ता विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान किए जाने हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि वह ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने के लिए विचार किए जाने से पहले, यह वचन देता है कि वह विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान किए जाने पर अधिवक्ता के रूप में अपना लाइसेंस तत्काल निलंबित करा लेगा और वह ऐसा उस रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही कर ले।

5. उच्च न्यायालय केवल ऐसे व्यक्तियों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करेगा जो उपर्युक्त योग्यता रखते हों और इसके द्वारा उपयुक्त पाए गए हों।
6. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो संहिता द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई हैं।
7. शक्तियों का प्रतिसंहरण- उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां संबंधित व्यक्ति से बिना किसी नोटिस या सुनवाई के प्रतिसंहरित की जा सकती हैं, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि ऐसा प्रतिसंहरण जनहित में है।
8. (1) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपना पदभार संभालने से पहले, न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए निर्धारित शपथ लेगा। यह शपथ सत्र न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी।  
(2) प्रत्येक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को सत्र न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालयी कार्य से परिचित कराने के लिए 15 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, परन्तु उच्च न्यायालय ऐसे किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण से छूट दे सकता है।  
(3) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, संहिता की योजना के अनुसार सत्र न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होंगे।
9. (1) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नियम 3 के उप-नियम (6) के अध्याधीन नवीकृत किया जा सकता है।  
(2) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले मानदेय और वास्तविक व्यय का हकदार होगा।
10. (1) राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श द्वारा सत्र न्यायाधीश के माध्यम से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय स्थल, वाहन और सहायक स्टाफ़ उपलब्ध कराएगी।  
(2) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा, जैसाकि न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनुमेय है।
11. (1) सभी लघु अपराधों का विचारण विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश न करे।  
(2) सभी लघु अपराधों का विचारण संहिता की धारा 283 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त रूप से किया जाएगा।

- (3) जब संक्षिप्त विचारण के दौरान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत हो कि मामले की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसका संक्षिप्त विचारण करना उचित नहीं है, तो वह मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास इसके निर्णयन हेतु किसी सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपने के लिए भेज देगा।
12. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को, उपरोक्त लघु अपराधों के संबंध में, जमानत और बंध-पत्र के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो संहिता में प्रदान की गई हैं।
13. निरसन और व्यावृत्तियाँ:-
- (i) दिल्ली लघु अपराध (विशेष महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण) नियम, 1998 एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं।
- (ii) ऐसे निरसन के बावजूद, 1998 के नियमों के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य या कार्रवाई को 2024 के नियमों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,  
कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

## HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

### NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2024

**No. 63/Rules/DHC**—In exercise of the powers conferred by proviso to sub – section (1) of Section 11 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and in supersession of the Rules made earlier under section 18 of *Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974)* by this Court, Hon'ble the Acting Chief Justice and Hon'ble Judges of the High Court of Delhi at New Delhi, hereby make the following Rules, namely:-

#### 1. Short title, extent and commencement :-

- (1) These Rules shall be called the Delhi Petty Offences (Trial by Special Judicial Magistrates) Rules, 2024.
- (2) They shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

#### 2. Definitions : - In these Rules, unless the context otherwise requires :-

- (1) “Sanhita” shall mean the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
- (2) “Offence” shall have the same meaning as assigned to it in the Sanhita.
- (3) (a) “Petty Offence” means an offence listed in the following provisions:-
  - (i) Section 359, Tables I & II, of the Sanhita, excluding offences under Section 79, 82(1), 88, 117(2), 122(2), 125(b), 127(3), 127(4), 127(6), 303(2), 306, 316(2), 316(3), 316(4), 317(2), 317(5), 318(2), 318(3), 318(4), 319(2), 322, 323, 325, 326(a), 347(2) and 351(3) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023;
  - (ii) Section 194 and 125 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023;
  - (ii) All offences under any other Act which are punishable upto two years' imprisonment.
- (b) The Chief Justice of the High Court may from time to time assign any other type of cases to be decided by the Special Judicial Magistrates.
- (4) Definitions given in Section 2 of the Sanhita shall hold good for these Rules.

#### 3. Qualification:- A person shall not be qualified for appointment as Special Judicial Magistrate unless he/she is a law graduate and

- (1) has been a District Magistrate or a Judicial Officer; or
- (2) has for a period of not less than one year exercised the powers of Sub-Divisional Magistrate; or
- (3) has for a period of not less than two years exercised the powers of an Executive Magistrate; or

- (4) has held, for a period of not less than five years, a Group 'A' post on the Establishment of the High Court of Delhi or that of the Courts Subordinate thereto; or
- (5) has held, for a period of not less than five years, a Group 'A' post under the department of the Government of NCT of Delhi or the Central Government or State Government (Preference will be given to those persons who have been dealing with legal affairs or have been working in the department dealing with legal affairs); and
- (6) has not attained the age of 65 years on the date of conferment of power of Special Judicial Magistrate on him/her.

**Explanation: -**

For the purpose of these rules a "law graduate" is a person who is eligible to be enrolled as an advocate.]

**4. Disqualification : A person –**

- (1) Who does not hold or has not held a post under the Govt./ High Court of Delhi and the Courts subordinate thereto of the rank and status and does not possess the qualification, if any, attached thereto, as mentioned in the just preceding Rule; or
- (2) Who having held an office under the State or the Union Government or the High Court and the Courts subordinate thereto, has been dismissed or removed or compulsorily retired from service or subjected to any other major penalty for misconduct' or
- (3) Who having held an office as mentioned in sub –rule (2) has been convicted and sentenced by a Court for an offence involving moral delinquency or is charged of any offence constituting moral turpitude and proceedings against him are pending; or
- (4) Who having held an office as mentioned in sub – rule (2), is of unsound mind or who is deaf or mute or blind or suffering from leprosy or any other contagious disease; or
- (5) Who having held an office as mentioned in sub – rule (2) has been adjudicated as an insolvent or an undischarged insolvent; or
- (6) Who having held an office as provided in sub– rule (1), (2), (3), (4) and (5) of Rule 3, is a practicing advocate;

shall not be eligible for conferment of powers of Special Judicial Magistrate.

Provided that a practicing advocate as mentioned in sub –rule (6), shall not be disqualified for conferment of powers of Special Judicial Magistrate, if he, before he is considered for such conferment, undertakes that he shall have his license as an advocate suspended immediately on conferment of power of Special Judicial Magistrate and does so before assumption of charge as such.

- 5. The High Court shall appoint only such persons as Special Judicial Magistrate who possess the qualification mentioned above and are found suitable by it.
- 6. The Special Judicial Magistrate shall exercise the same powers as conferred by the Sanhita on Judicial Magistrates.
- 7. Revocation of powers – The powers of Special Judicial Magistrate conferred on a person by the High Court are liable to be revoked without any notice or hearing to the person concerned, if the High Court is satisfied that such revocation is in public interest.
- 8. (1) A Special Judicial Magistrate, before entering upon his office, shall take oath as has been prescribed for a Judicial Magistrate. The oath shall be administered by the Sessions Judge.
- (2) Every Special Judicial Magistrate shall be imparted 15 day's training to familiarize himself with the working of Courts by the Sessions Judge/Chief Judicial Magistrate provided that the High Court may exempt any such Special Judicial Magistrate from training.
- (3) Special Judicial Magistrate shall be under the control of Sessions Judge and the Chief Judicial Magistrate, as per the scheme of the Sanhita.
- 9. (1) The term of the office of the Special Judicial Magistrate shall be one year which may be renewed by the High Court, subject to sub –rule (6) of Rule 3.

- (2) A Special Judicial Magistrate shall be entitled to such honorarium and out of pocket expenses, as may be fixed by the High Court from time to time.
10. (1) The State Government shall provide court accommodation, conveyance and ancillary staff through the Sessions Judge to the Special Judicial Magistrate in consultation with the Chief Justice of the High Court.
- (2) A Special Judicial Magistrate shall be entitled to only casual leave as may be permissible to a Judicial Magistrate.
11. (1) All petty offences shall be tried by Special Judicial Magistrates unless the High Court otherwise directs.
- (2) All petty offences shall be tried in a summary way as per procedure laid down in Section 283 of the Sanhita.
- (3) When in the course of summary trial it appears to the Special Judicial Magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, he shall refer the case to Chief Judicial Magistrate for entrusting it to any Judicial Magistrate competent to decide the same.
12. Special Judicial Magistrates, in relation to petty offences mentioned above, shall have the same powers as to bails and bonds as are provided in the Sanhita.
- 13. Repeal and Savings:-**
- (i) Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrates) Rules, 1998 are hereby repealed.
- (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Rules, 1998 shall be deemed to have been done or taken under the Rules, 2024.

By Order of the Court,

KANWAL JEET ARORA, Registrar General